पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की

आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता : मुख्यमंत्री

पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह परिणामोन्मुख, व्यावहारिक, तकनीक आधारित और समयानुकूल बनाया जाए

रोल आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से विकसित किया जाए

लखनऊ : 28 मई, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में पुलिसिंग केवल कानून–व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह परिणामोन्मुख, व्यावहारिक, तकनीक आधारित और समयानुकूल बनाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस दक्षता, अनुशासन, संवेदनशीलता और जनविश्वास के मानकों पर देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में स्थापित हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग हो तथा प्रशिक्षण का नियमित मूल्यांकन किया जाए। पुलिसकर्मियों को केवल कानून लागू करने तक सीमित न रखते हुए उन्हें संवाद कौशल, मानवीय व्यवहार और तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के अन्तर्गत पुलिस अकादमी मुरादाबाद, 11 प्रशिक्षण संस्थान, 06 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, 02 आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग संस्थान तथा 62 अस्थायी एवं 31 स्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेण्टर संचालित हैं। 112 आर0टी0सी0 पर एक साथ 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर अन्तिम परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराया गया है तथा एक साथ परीक्षा परिणाम घोषित किए गए।

प्रशिक्षण क्षमता को 18 हजार से बढ़ाकर 60,244 तक किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उच्चीकरण किया गया है तथा बाह्य विषयों में आवधिक मानक निर्धारित कर गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराई जा रही है और 5,000 विशेषज्ञ प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 'मिशन कर्मयोगी' के अन्तर्गत iGOT पोर्टल पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 27 मई, 2026 तक 3,90,799 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं तथा 59,02,703 कोर्स पूर्ण किए जा चुके हैं। 20 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस की 149 इकाइयों का iGOT पोर्टल पर सृजन कराया गया, जिससे जनपद, वाहिनी और इकाई स्तर पर प्रशिक्षण का प्रभावी पर्यवेक्षण सम्भव हुआ है।

बैठक में बताया गया कि 02 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित 'साधना सप्ताह' में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश की समस्त राज्य पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अकेले 28 लाख से अधिक कोर्स पूर्ण किए, जो कई राज्यों के समस्त विभागों के संयुक्त प्रदर्शन से भी अधिक रहा। इस अवधि में 2,61,032 कर्मियों ने 02 घण्टे से अधिक तथा 2,16,724 कर्मियों ने 04 घण्टे से अधिक का लर्निंग समय पूरा किया। 2,45,645 कर्मियों ने ए0आई0 कोर्स भी पूर्ण किए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि रोल आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से विकसित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ हुए एम0ओ0यू0 के तहत नवम्बर, 2025 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 34 पुलिस उपाधीक्षकों को 'एम0ए0 इन पुलिस साइंस एण्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेण्ट' की डिग्री प्रदान की गई। वहीं मई, 2026 में पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 47 उपनिरीक्षकों को 'पी0जी0 डिप्लोमा इन पुलिस एण्ड सिक्योरिटी मैनेजमेण्ट' प्रदान किया गया।

बैठक में आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 4,253 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 15,131 आरक्षी पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस, 2,282 महिला पी0ए0सी0 आरक्षी, 10,469 आरक्षी नागरिक पुलिस तथा 1,341 यू0पी0एस0एस0एफ0 आरक्षियों सहित बड़ी संख्या में कार्मिकों का आधारभूत प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इसके साथ ही 4,500 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डरों के प्रस्तावित प्रशिक्षण के

लिए विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर 11 संवेदनशीलता मॉड्यूल जोड़े गए हैं। ए0टी0एस, एस0टी0एफ0, एन0डी0आर0एफ, एस0डी0आर0एफ0, आर0ए0एफ0, यू0पी0–112, विमेन पावरलाइन, चाइल्डलाइन, बी0डी0एस0 और फायर सर्विसेज जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा ऑपरेशनल मॉक ड्रिल और कैप्सूल कोर्स संचालित किए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश किया जा रहा है। इसके तहत ड्रोन प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक लैब, ड्राइविंग सिम्युलेटर और फायरिंग सिम्युलेटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से अतिथि विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार ही पुलिस की वास्तविक पहचान बनाता है। बैठक में बताया गया कि जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत वाले 5,816 पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके लिए संवाद कौशल एवं सौम्य व्यवहार का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी0आई0एस0एस0) मुम्बई द्वारा 03 से 05 फरवरी, 2026 तक 37 पुलिसकर्मियों को Behaviour, Operational Soft Skills एवं Caselets का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिला सम्मान, संवाद क्षमता, आत्मनियंत्रण, तनाव प्रबन्धन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील व्यवहार जैसे 18 प्रमुख बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में मालदीव पुलिस सेवा के उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के माध्यम से विचारार्थ भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसे भारत और पड़ोसी देशों के बीच आंतरिक सुरक्षा सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्रणाली में निरन्तर नवाचार, जवाबदेही और आधुनिकता सुनिश्चित की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस हर चुनौती का सामना अधिक दक्षता, संवेदनशीलता और प्रोफेशनल क्षमता के साथ कर सके।

————————